

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 767 बैठक दिनांक 10/06/2024 को डॉ.पी.सी.दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. P-2/483/24 ShriAshishTiwari S/o ShriBalkrishanTiwari, NIWASI NAVALPUR, TEHSIL SOHAGPUR, DISTRICT SHAHDOL, (M.P.)-461771. Prior Environment Clearance for "Dhangawan Stone (Gitti) Quarry Lease "Khasra No.- 1728/1, an Area of 4.0 Ha. located Near Village- Dhangawan, Tehsil- Gohparu, District- Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity - 25,137 Cum/Year. [MIN/452836/2023.]**

प्रकरण आज सेक की 767वीं बैठक दिनांक 10/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक /उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुये समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा। **ADS**

2. **Case No. P-2/539/24 Shri Krishna Singh, Ro/- Village -Jamui, Tehsil- Sohagpur, District-Shahdol, (M.P.) - 484001 Prior Environment Clearance for Jamua Stone (Gitti) Quarry Khasra No.- 65(P)], an Area of 2.00 Ha. located Near Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity - 27,297 Cum/Year. [MIN/ 463185 /2023.]**

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Krishna Singh, Ro/- Village -Jamui, Tehsil- Sohagpur, District-Shahdol, (M.P.) - 484001. Prior Environment Clearance for Jamua Stone (Gitti) Quarry Khasra No.- 65(P),, an Area of 2.00 Ha. located Near Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 27,297 Cum/Year. <b>SIA/MP/MIN/ 463185 /2023.</b>	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 65(P),	एरिया- 2.00 ha., निजीभूमि
परियोजना स्थल	Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.)	
Activity	It is Fresh B2 Category Stone Quarry Project Making Gitti through Crusher Plant. Project is located at Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol Madhya Pradesh Total Quarry Lease Area - 2.00Ha.	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 73071 दिनांक 03/10/2023.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting,	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	● <b>स्टोन – 27,297 घनमीटर/वर्ष।</b>	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शहडोल</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदाने स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा <b>2.00</b> हे. होता है, अतः प्रकरण <b>बी-2</b> श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शहडोल</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शहडोल</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – गोरतरा, जिला – शहडोल द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र०. 01 दिनांक 08/07/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09/01/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
----------------------------------	--

प्रकरण सेक की 748 वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

आज सेक की 767 वीं बैठक दिनांक 10/06/2024 में प्रकरण को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Krishna Singh, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.एस.जी इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र खुदा हुआ है। अतः जिला खनिज अधिकारी से स्वीकृत खदान में कोई खनन कार्य नहीं हुआ के संबंध में सप्ट अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायें, तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा। **ADS**

**3. Case No. 10957/2023 ShriRamakantPandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mangarh River Sand Mine in an area of 9.46 ha. (56760 cum per year) (Khasra No. 1043, 1103), Village-Mangarh, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP) [448389] Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)854-,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 580 मीटर पर पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

4. **Case No. 10952/2023 ShriRamakantPandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Menhda Sand Mine in an area of 10.00 ha. (62000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Mehda, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP) [448354]**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 485 मीटर पर पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया,

767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024

स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

5. **Case No. P2/189/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - PACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum [ MIN/460218/2024]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

6. **Case No. P2/195/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI-B, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum [ MIN/450085/2023]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ)

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

7. **Case No. 11291/2024 ShriBalaMehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Chhitipur Sand Quarry Deposit in an area of 5.10 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 181), Village-Chhitipur, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [449976]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

'परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 300 मीटर पर पक्का मेजर रोड ब्रिज एवं 186 मीटर पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड ब्रिज एवं स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें। ADS

8. **Case No. P2/191/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - CHHIPANER, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum [ MIN/460179/2024] Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-ए-वी बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं । संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी । (ADS)

9. **Case No. 11294/2024 ShriBalaMehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mahowadamron Sand Quarry Deposit in an area of 12.650 ha. (1802625 cum per year) (Khasra No. 1488), Village-MahobaDamron, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP) [449965]**

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024**

**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-ए-वी बैठक दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो-बीच एक रपटा रोड ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रपटा रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

**10. Case No. P2/190 /24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - LACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum [ MIN/460202/2024]**

**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-ए-वी बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।



767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

**11. Case No. P2/188 /24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 20.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - HANDIYA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [ MIN/460233/2024]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-ए-वी बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

**12. Case No. P2/187 /24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-**

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

**Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - MANOHARPURA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [ MIN/460257/2024]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

**13. Case No. P2/185 /24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - GOYAT, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum [MIN/460313/2024]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

**14. Case No. P2/193 /24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - MALPONE, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [ MIN/450140/2023] Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

**15. Case No. P2/186/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - AAJNAI, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum [ MIN/460286/2024]**

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं । संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी । (ADS)

**16. Case No. P2/192/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 22.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - Uchan, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 66000 cum per annum [ MIN/450156/2023]**

**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ. ए. 66/2024 एवं ओ. ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अवगत कराया है कि हरदा जिले में माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए.

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024**

66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधीन उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ADS)

**17. Case No. 11296/2024 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Kumharra Sand Quarry in an area of 5.50 ha. (16500 cum per year) (Khasra No. 194), Village-Kumharra, Tehsil-Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP) [450427] Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधरिण प्राधिकरण (SEIAA) 854,-वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 95 मीटर पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

**18. Case No. P2/382 /24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 4.500 Hectare, Khasra No.- 483, in Village - BHADPURA, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 4000 cum per annum [ MIN/444513/2023]**  
**Referred Back**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 858वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

'परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से लगभग 630 मीटर की दूरी पर के एक पक्का रोड परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी (1 कि. मी.) छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, पुल, पुलिया, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

**19. Case No. P2/384/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 12.785 Hectare, Khasra No.- 124, in Village - JUGPURA, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 80000 cum per annum [ MIN/444546/2023]**  
**Referred Back**

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 858वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान एक अन्य खदान प्रकरण क्र. 11231 के अंदर ओवरलेप होना परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः जाये। परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया

**प्रकरण को आज दिनांक 10/06/2024 को समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-**

प्रस्तावित खदान एक अन्य खदान प्रकरण क्र. 11231 के अंदर ओवरलेप परिलक्षित होने के संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी डीएसआर के कॉर्डिनेट एवं माईनिंग प्लान के अनुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये पुनः प्रस्तुत किया जावे ।

**ADS- खदान की सीमा के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये पुनः प्रस्तुत किया जावे**

**20. Case No. P2/351 JITENDRA CHANDEL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.700 Hectare, Khasra No.-01, 167, 210, in Village - Malegaon, Tehsil - Sausar, District - Chhindwara (MP), Maximum Production - 156600 cum per annum [ MIN/445818/2023] (Query)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री जितेन्द्र सिंह चंदेल कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 1,167, 210 ( तासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 8.70 हे.
स्थल	ग्राम – मालेगांव, तहसील – साँसर, जिला –	

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

	छिंदवाड़ा (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मालेगांव रेत खदान, दिनांक- 24/09/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा मालेगांव रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,56,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,56,600 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1130 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 8.70 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1130 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1130 दिनांक



**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

	25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेชัน/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालेगांव जिला छिंदवाड़ा के अनापत्ती पत्र दिनांक 05/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	कन्हान नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	25/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-56 के सरल क्रमांक-57 एवं पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई।  आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। सेक की मितिग 762-बी दिनांक 03/06/2024 में जारी एडीएस के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त पत्र क्रमांक 792 दिनांक 08/06/2024 के अनुसार खसरा न. 210 रकबा न. 1.3870 हे. में आवागमन का मार्ग है, अतः रेत खनन प्रतिबंधित किया जाता है। खसरा न. 01,167 जिसका कुल रकबा 6.00 हे. है, एवं गहराई डीएसआर के अनुसार 0.6

## 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक दिनांक 10 जून 2024

मी. दर्शाई गई है के अनुसार दोनों खसरों का क्षेत्रफल एवं गहराई को ध्यान में रखते हुये कुल उत्पादन क्षमता का 60 प्रतिशत सेंड माईनिंग गाईडलाईन के अनुसार 21600 घन मी/प्रतिवर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 21600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लीज क्षेत्र का खसरा न. 210 रकबा न. 1.3870 हे. में आवागमन का मार्ग है, अतः रेत खनन प्रतिबंधित किया जाता है।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

S.No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	2,70,000	1,00,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3000 X 150 = ₹4,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300 X 500 = ₹1,50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(7100 X 50 = ₹ 3,55,000)	
		9,55,000	1,50,480
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @ 500/truck (73 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	73,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 84	70,000	14,000

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 84 Labors - 84× 500 × 2)	-	84,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	40,000	4,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 84 workers - 84 × 1500)	94,500	50,000
12	Shelter rooms for labors (30*20 ft) =600 Square feet	3,00,000	50,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	6,00,000	3,60,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	
<b>Total</b>		<b>24,52,000/-</b>	<b>11,96,480/-</b>

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 2,30,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बारादेवीखापा के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला	2,30,000

**767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक**  
**दिनांक 10 जून 2024**

विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	
<b>कुल</b>	<b>2,30,000/-</b>

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7100 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	7100
<b>कुल</b>			<b>10400</b>

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
  - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
  - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं

767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक  
दिनांक 10 जून 2024

होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक दिनांक 10 जून 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with at least 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland



# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
  38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
  39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### **Annexure- 'C'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

## 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक दिनांक 10 जून 2024

- exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
  7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
  8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
  9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
  10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
  11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
  12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
  13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
  14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

## 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक दिनांक 10 जून 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
  37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

**खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-**

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 - 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 - 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		



# 767वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकी बैठक

## दिनांक 10 जून 2024

	तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम ढतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे